गुजरात के कुल कितने क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना गया ,

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इसमे से कितने क्षेत्र का विद्युतीकरण करने के लिए गुजरात राज्य को सहायता दी है , और

(ग) सहायता की कितनी राशि दी गई और कितने ग्रामो का विद्युतीकरण किया गया और अभी कितने ग्रामो का विद्युतीकरण होना है तथा कब तक इन ग्रामो का विद्युतीकरण हो जाने की सभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) हाथी समिति ने गुजरात के 184 तालुको (1, 08, 267 वर्ग किमी०) मे से 114 तालुको (12, 652 वर्ग किमी०) को आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना है।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने अब तक 48 योजनाओ को स्वीकृति दी है। इनमे, पाच वर्षों मे, 1,498 नए गावो का विद्युतीकरण करने की संकल्पना है।

(ग) उपर्युक्त 48 योजनाओ पर 1,523 681 लाख रुपए की लागत आएगी। 30 नवम्बर, 1977 तक, 886 गावो को बिजली दी जा चुकी थी और 612 नए गाव आगामी पाच वर्षों मे विद्युतीकृत कर दिए जाएगे।

### Rise in Price of Paper

1936 SHRI MOHINDER SINGH SAIYANWALA Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state

(a) whether it is a fact that a warning has been given to the paper industry to behave itself regarding *price rise and irregularities in production*;

(b) whether some discussions with the industry were held in this regard; and

(c) if so, the results thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) to (c) Although there is no statutory control on prices of paper, Government have been discouraging the industry from resorting to unilateral increase in prices without adequate justification Government's unhappiness at *the price increase effected by* some mills without consulting Government was conveyed to the paper industry at a meeting held in January, 1978. By and large the industry has abided by Government's instructions but certain mills have tried to justify the price increase Government has stressed that the 1977 price level should be restored before the question of any revision is considered The reaction of the industry is awaited before Government takes suitable regulatory measures to control the price situation

### सूचना मंत्री की स्टाफ आर्टिस्टो के साथ उनकी समस्याओ के बारे में बातचीत

1937. श्री नवाब सिह चौहान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 7 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न सख्या 2941 के उत्तर के सबध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) स्टाफ आर्टिस्टो द्वारा प्रस्तुत मागो के बारे मे क्या कार्रवाई की जा रही है ,

(ख) जनता सरकार के सत्ता मे आने के बाद उन्हे क्या सुविधाए प्रदान की गई ,

(ग) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी के आर्टिस्टो को नौकरशाही से मुक्त करने का है जिससे वे अपने कार्यक्रम सबन्धी दायित्व सुचारु रूप से पूरे कर सके, और

(घ) यदि हा, तो कब तक और उनके लिए पदोन्नति के अवसरो की कब तक व्यवस्था की जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टो की सेवा शर्तें

पेंशन को छोड़ कर नियमित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के लगभग समान है। स्टाफ आर्टिस्ट, पेंशन के बदले में, अंशदायी भविष्य निधि के हकदार है, अब भी नियमित सरकारी कर्मचारियो के लिए अतिरिक्त महगाई भत्ता मजूर किया जाता है, उसको स्टाफ आर्टिस्टो पर भी लागू किया जाता है।

स्टाफ आर्टिस्टो के वेतनमानो मे आकाशवाणी के तुलनीय श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियो के वेतनमानो के सबध म तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशो के अनुरूप जन, 1976 मे सशोधन किया गया था। कुछ श्रेणियो के स्टाफ आर्टिस्टो ने अपने वेतनमानो मे और सशोधन करने की माग की है, परन्तु ऐसी मागो को पूरा करना सभव नही हुआ है।

तुलनीय श्रेणियो के सरकारी सिवल पदों के ढाचे पर स्टाफ आर्टिस्टो को सलेक्शन ग्रेड देने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) और (घ). स्टाफ आर्टिस्टों को किसी भी नियत्रण के अधीन रखने का कोई इरादा नही है, सिवाय उस हद तक जो समय समय पर सरकारी नीति के ढाचे के अन्तर्गत जन हित म आवश्यक हों। विभिन्न श्रेणी के स्टाफ आर्टिस्टो के लिए बनाए गए भर्ती नियमो के अनुसार स्टाफ आर्टिस्ट पदोन्नति के पात्र है।

**Reunification of Nagas, Mizo and Manipuri People into States of their own**

1938 SHRI PURNA SINHA Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there are demands from Nagas, Mizos and Manipuris of the State of Nagaland and Manipur as also of Mizoram for unification or reunification of Naga, Mizo and Manipuri peoples into State of their own;

(b) whether Government propose to accept the demands of the Nagas, Mizos and Manipuris to put their respective races and tribes within States of their own on the basis of their difference as distinct ethnic groups; and

(c) if so, when?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI S D PATIL): (a) to (c). Various such demands have been received from time to time. However, the Government is at present not seized of any proposal for the reorganisation of States

**Directive to States for Reservation in Services**

1939 SHRI G Y KRISHNAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state·

(a) whether some States have reserved quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Government services;

(b) if so, the names of such States and the percentage of quota so reserved,

(c) whether any directive has also been issued from the Central Government to the States in this regard; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI S D PATIL)· (a) and (b). Reservations in State services is a matter within the competence and jurisdiction of the respective State Governments The Central Government are aware that in several State Governments, reservations have been provided in State services for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Complete and up-to-date information in this regard is, however, not readily available.

(c) and (d). Reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services under the State Governments being the concern of the respective State Governments, in terms of Article 335 read with Article